वेतन संशोधन - बीएसएनएलईयू को बलि का बकरा न बनाएं।

संपादकीय, बीएसएनएल स्वर, मई 2024

वेतन संशोधन बीएसएनएल कर्मचारियों का वैध अधिकार है। बेशक, सरकार तीसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों का हवाला देकर इसे नकार रही है। तीसरी पीआरसी की सिफारिशों ने घाटे में चल रहे पीएसयू के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन को असंभव बना दिया है। वहीं, वेतन संशोधन पर डीपीई की सिफारिशें पीएसयू के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने सीएमडी बीएसएनएल को नॉन-एग्जीक्यूटिवों की मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे मंजूरी के लिए भेजने का निर्देश दिया है।

दूरसंचार विभाग के इस पत्र के आधार पर, बीएसएनएल में नॉन-एग्जीक्यूटिवों के लिए संयुक्त वेतन वार्ता समिति का गठन किया गया है। शुरुआत में, प्रबंधन ने उचित रुख अपनाया और 27.07.2018 को नॉन-एग्जीक्यूटिवों के नए वेतनमान को अंतिम रूप दिया। लेकिन, जुलाई, 2019 में नए सीएमडी बीएसएनएल के कार्यभार संभालने के बाद चीजें पूरी तरह बदल गईं। इसके बाद, वेतन वार्ता समिति में आपसी सहमति से पहले से तय वेतनमान को कूड़ेदान में फेंक दिया गया।

इसके अलावा, प्रबंधन पक्ष के प्रतिनिधि वेतन वार्ता समिति में अस्वीकार्य शर्तें लगा रहे हैं। ये शर्तें हैं वेतनमान में कमी, 0% फिटमेंट, भत्तों में संशोधन नहीं - यहां तक कि एचआरए में संशोधन नहीं और 01.01.2017 से केवल नाममात्र का वेतन संशोधन, जिसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों ने ठहराव के कारण अपनी वेतन वृद्धि खो दी है, उन्हें भी कोई बकाया नहीं मिलेगा। यदि घटा हुआ वेतनमान स्वीकार कर लिया जाता है, तो ठहराव की समस्या स्थायी हो जाएगी।

ऐसी स्थिति में, बीएसएनएलईयू और एनएफटीई दोनों को प्रबंधन पर दबाव बनाने के लिए ट्रेड यूनियन कार्रवाई का आयोजन करना चाहिए। लेकिन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनएफटीई किसी भी संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। बीएसएनएलईयू ने 16 फरवरी, 2024 को एक दिवसीय सफल हड़ताल का आयोजन किया। यह हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान के साथ हुई। फिर भी, बीएसएनएलईयू ने हड़ताल का आयोजन पूरी तरह से बीएसएनएल कर्मचारियों के मुद्दों पर किया। इस हड़ताल में वेतन संशोधन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। हड़ताल के आह्वान को कर्मचारियों की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। एनएफटीई को भी इस हड़ताल में शामिल होना चाहिए था। लेकिन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएलईयू द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बावजूद एनएफटीई ने इस हड़ताल में शामिल होने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनएफटीई वेतन संशोधन के न होने के लिए बीएसएनएलईयू को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रही है। वह एक शरारतपूर्ण प्रचार कर रही है कि वेतन संशोधन केवल इसलिए तय नहीं हुआ है क्योंकि बीएसएनएलईयू के महासचिव समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे हैं। यह कर्मचारियों को बेवकूफ बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। प्रबंधन की सभी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के बाद भी वेतन संशोधन तय नहीं होगा। क्योंकि, किसी भी वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।

वेतन संशोधन का निपटारा न होने से नॉन-एग्जीक्यूटिवों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नॉन-एग्जीक्यूटिवों का एक बड़ा हिस्सा ठहराव से पीड़ित है, जिसके परिणामस्वरूप हर महीने हजारों रुपये का नुकसान हो रहा है। बीएसएनएलईयू और एनएफटीई बीएसएनएल में दो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन हैं। इन यूनियनों को पीएंडटी ट्रेड यूनियन आंदोलन की जुझारू परंपरा विरासत में मिली है। दोनों यूनियनें सरकार की आर्थिक नीतियों का कड़ा विरोध करती हैं। ऐसे में बीएसएनएलईयू और एनएफटीई दोनों का यह कर्तव्य है कि वे गंभीर संघर्षों को संगठित करने और वेतन संशोधन के निपटारे के लिए दबाव बनाने का बीड़ा उठाएं।

*****